



भारत INDIA

विश्व मितव्ययिता दिवस

स्मारक डाक-टिकट

WORLD THRIFT DAY

COMMEMORATION STAMP

31-10-1971

प्रति वर्ष 31 अक्तूबर का दिन विभिन्न देशों में विश्व मितव्ययिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बचत संस्थाएं और कार्यकर्त्ता मानवीय सुख-समृद्धि की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बचत के आदर्श में अपनी निष्ठा की पुनःप्रतिष्ठा करते हैं।

इस नई प्रक्रिया का आरम्भ सन् 1924 में हुआ। इसी वर्ष, मिलान में हुई अन्तर्राष्ट्रीय बचत बैंक कांग्रेस ने अपनी बैठक के आखिरी दिन 31 अक्तूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की थी। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ बचत की आदत और उसके प्रचार पर विशेष बल दिया गया, साथ ही इस बात पर भी जोर डाला गया कि 31 अक्तूबर का दिन अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मितव्ययिता को प्रोत्साहन देने के लिए खास तौर से मनाया जाय।

विश्व मितव्ययिता दिवस का महत्त्व इस रूप में है कि यह जनता के साथ सम्पर्क बढ़ाने का अनन्य अवसर प्रदान करता है। यह एक ऐसा दिन है, जबकि बचत बैंकों का बेहद प्रचार होता है और बूढ़े व जवान इससे सम्बन्धित उत्सवों में भाग लेने के लिए बचत बैंकों की ओर लपकते हैं। विश्व मितव्ययिता दिवस बचत बैंक के तमाम कर्मचारियों के मन में जन-सेवा-कार्य के महत्त्व की छाप बैठाने का सुअवसर प्रदान करता है।

भारत में, राष्ट्रीय बचत संगठन का विश्व मितव्ययिता दिवस की गतिविधियों से निकट

संबंध रहा है। इस दिन वार्षिक राष्ट्रीय बचत पखवाड़े का उद्घाटन किया जाता है।

भारत में पहली बचत संस्था की नींव सन् 1833 में रखी गई थी, जबकि “प्रत्येक वर्ग (ब्रिटिश और देशी) की बचतों की पूंजी लगाने” के लिए कलकत्ता में प्रेसीडेंसी बैंक की स्थापना की गई थी। बाद में, मद्रास और बम्बई के प्रेसीडेंसी बैंकों ने क्रमशः 1834 और 1835 में बचत जमाओं को स्वीकार करना शुरू कर दिया। 1860 के बाद के दशक में डाक बचत बैंकों के नमूने पर, जिन्होंने कि इंग्लैंड में बड़ी सफलता के साथ काम किया था, इस योजना का सारे भारत में विस्तार करने के प्रश्न पर विचार किया गया। इस प्रकार, एक साधारण आदमी को बचतों के रूप में पूंजी लगाने की सुविधा देने और उसके बाद बचत की आदत को प्रोत्साहन देने के प्राथमिक उद्देश्य को लेकर सन् 1881 में डाकघर बचत बैंक का शुभारम्भ हुआ। अलबत्ता, दूसरे विश्व-युद्ध तक जनता की बचतों का संग्रह करने के लिए कोई संगठित आंदोलन नहीं हुआ था।

अक्तूबर 1943 में, मुख्यतः मितव्ययिता को प्रोत्साहन देने के लिए, द्वितीय विश्व-युद्ध काल में अर्थ-व्यवस्था में उत्पन्न हुई मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियों के निराकरण के लिए और युद्ध सम्बन्धी कार्यों को वित्तीय सहायता देने की दृष्टि से निधि एकत्र करने के लिए, भारत सरकार ने थोड़े-से कर्मचारियों के साथ शिमला में राष्ट्रीय

बचत केन्द्रीय व्यूरो की स्थापना की। देश के साधनों के नियमित संग्रह में प्रांतीय सरकारों के सहयोग से इस व्यूरो द्वारा प्राप्त किए गये उत्साहवर्द्धक परिणामों को देखते हुए भारत सरकार ने इस आंदोलन में जन-रुचि को बनाए रखने और उसे विकसित करने के लिए मई, 1948 में बचत आंदोलन का पुनर्गठन किया। अब देश में एक पूर्ण विकसित बचत संगठन काम कर रहा है, जिसके प्रधान राष्ट्रीय बचत आयुक्त हैं और राज्य, डिवीजन तथा जिला स्तरों पर कई क्षेत्रीय और दूसरे कार्यालय हैं। जनता के विभिन्न वर्गों की जरूरतों के अनुसार अनेक प्रकार के बचत बैंक खाते और बचत प्रमाण-पत्र (जिनमें से कुछ में कर में आकर्षक रियायतें होती हैं), प्रस्तुत किए जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ नई योजनाएं शुरू की गई हैं, ताकि इन्हें समाज के सभी वर्गों के लिए और भी आकर्षक बनाया जा सके। समय-समय पर चलाये जाने वाले आंदोलनों के अलावा अनेक प्रकार की अल्प बचत योजनाओं के लिए राष्ट्रीय बचत संगठन सभी माध्यमों के द्वारा अनवरत और अत्यधिक प्रचार-प्रसार करता है। राज्य सरकारें, जो कि इस आंदोलन की प्रगति में प्रमुख रूप से रुचि रखती हैं (क्योंकि उन्हें अपने विकास कार्यक्रमों के लिए कुल संग्रह का एक बड़ा भाग ऋण के रूप में दिया जाता है), वे भी अल्प बचत योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम में सक्रिय भाग लेती हैं। योजना के अनेक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के

लिए देश के आंतरिक साधनों के संग्रह के महत्वपूर्ण काम में राष्ट्रीय बचत संगठन को एक बड़ी संख्या में अधिकृत एजेंटों, स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं, सरकारी कर्मचारियों और शीर सरकारी लोगों का सहयोग भी प्राप्त है। जमा के संग्रह में की गई प्रगति काफी सन्तोषजनक रही है। 1970-71 के दौरान संग्रह की गई कुल रकम 200 करोड़ रुपये से कुछ ही कम रही है। विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली कुल देय रकम 2,200 करोड़ रुपये से कुछ ऊपर बैठती है और यह देश के आंतरिक ऋण का लगभग 29 प्रतिशत है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया और डाकघर, जनता की प्रतिभूतियां वेचकर इस आंदोलन को चलाते हैं और पूंजी लगाने वालों की सेवा करते हैं। यहां इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में डाकघरों के द्वारा शांत और सादे ढंग से की जा रही महान् सहायता का स्मरण करना उचित होगा। डाकघर बचत बैंकों की संख्या, जो इस शताब्दी के प्रारम्भ में मुश्किल से 6,500 थी, अब बढ़कर एक लाख से अधिक हो गई है। देश के तमाम डाकघरों में से लगभग 90 प्रतिशत को बचत बैंक के लेन-देन का काम करने का अधिकार है और ऐसी आशा है कि जल्दी ही बाकी 10 प्रतिशत डाकघरों को भी बचत बैंक का काम करने की शक्तियां दे दी जाएंगी। इन डाकघर बचत बैंकों में से अधिकांशतः ग्रामीण अथवा अर्द्धशहरी जनता की सेवा करते हैं, जहां कि अभी

हाल तक बहुत ही कम व्यापारिक बैंकों ने काम करने का साहस किया है। इस प्रकार हरित क्रांति और गांवों की बढ़ती हुई खुशहाली के संदर्भ में राष्ट्र-निर्माण के कार्य के लिए बचे हुए धन को बटोरने में डाकघर बचत बैंक सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। उसके पास बचत बैंक और दूसरे खातों में जमा के रूप में तथा बचत प्रमाण-पत्रों की देय राशि के रूप में 2,221 करोड़ रुपये की रकम है। जमाकर्ताओं की संख्या 2.4 करोड़ से अधिक है।

बचत, प्रत्येक नागरिक के लिए गुणवत्ता एवं अनुशासन की द्योतक है। अनुमोदित अल्प बचत योजनाओं के अंतर्गत बचत करना और पूंजी लगाना केवल बचत करने वाले की ही सहायता नहीं करता, बल्कि देश की भी सहायता करता है, जिसे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बढ़ती हुई दर को प्राप्त करने और मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति के निराकरण हेतु राष्ट्र-निर्माण की विभिन्न योजनाओं के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं।

डाक-तार विभाग मितव्ययिता की आदतों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और दुनिया भर में मनाये जा रहे आयोजनों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए विश्व मितव्ययिता दिवस के अवसर पर विशेष स्मारक डाक-टिकट निकाल कर अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता है।

31st of October every year is observed in many countries as the World Thrift Day. On this day, savings institutions and workers revive their faith in the ideal of thrift as a step to human happiness.

The origin of this innovation goes to the year 1924. In that year, the International Savings Bank Congress held in Milan, proclaimed the last day of their meet, 31st October, to be observed as World Thrift Day. The resolution, among other things, emphasised the practice and propaganda of saving, and that 31st October would be specially devoted to the promotion of thrift from an International standpoint.

The significance of the World Thrift Day is that it provides a unique opportunity to strengthen the ties with the public. It is a day on which the savings banks stand in full light of publicity, when young and old hurry, to the savings banks in order to take part in the festivities. World Thrift Day provides an opportunity to impress on the entire savings bank staff the importance of the task of rendering service to the public.

In India, the National Savings Organisation has been closely associated with the activities of the World Thrift Day. The annual National Savings Fortnight is inaugurated on that day.

The foundations for the first savings institution in India were laid in the year 1833 when the Presidency Bank in Calcutta was established to provide for "the investment of the savings of all classes—British and native". Later, the Presidency Banks at Madras and Bombay started accepting savings deposits in 1834 and 1835, respectively. In the 1860's the question of extension of the scheme to the whole of India was considered, modelling on the Postal Savings Banks, which worked with "great success" in England. Thus, the Post Office Savings

Bank came into being in 1881 with the primary object of providing facility of investment of the savings to the common man thereby encouraging the habit of thrift. However, there was no organised savings movement as such in existence in India to work for the mobilisation of savings of the people till the Second World War.

In October, 1943, the Government of India set up the National Savings Central Bureau in Simla with a small staff primarily to promote thrift, to counteract the inflationary trends caused in the economy during the Second World War and to collect funds to finance the war efforts. With the encouraging results achieved by this Bureau with the co-operation of the Provincial Governments in the steady mobilisation of resources in the country, the Government of India reorganised the savings movement in May, 1948, in order to sustain and develop public interest in the movement. A full-fledged national savings organisation now functions in the country with the National Savings Commissioner as its head and a number of regional and other offices at the State, Divisional and District levels. Various types of savings bank accounts and savings certificates (some of them with attractive tax concessions) are offered to cater to the needs of different sections of the people. Very recently, new schemes have been introduced so as to make them more attractive for all classes of societies. In addition to campaigns undertaken periodically, the National Savings Organisation undertakes continuous and intensive publicity and propaganda through all media for the various small savings schemes. The State Governments who have also a vital interest in the progress of the movement (inasmuch as they are given a major share of the net collections as loans for their developmental programmes) also actively participate in the

programmes for popularisation of small savings schemes. The National Savings Organisation has also the co-operation of a large number of authorised agents, voluntary workers, officials and non-officials, in this important task of mobilisation of internal resources of the country for the successful execution of various plan programmes. The progress made in deposit mobilisation has been very satisfactory. During 1970-71, the net collections amount to a little less than 200 crores of rupees. The total outstandings under the various small savings schemes now stand at a little over Rs. 2,200 crores and these form about 29 per cent of the country's internal debt.

The State Bank of India and the post offices serve the movement in selling these securities to the public and render service to the investors. It will be worthwhile recalling here the yeoman service rendered by the post offices in a silent and unostentatious way in this national endeavour. The number of post office savings banks in the country which was hardly 6,500 at the beginning of the century, has now exceeded a lakh. Nearly 90% of all the post offices in the country are authorised to transact savings bank business and it is hoped very shortly to vest the remaining 10 per cent of the post offices also with powers to do savings bank work. Most of these post office savings banks serve rural or semi-urban communities where, till recently, very few commercial banks ventured. Thus, in the context of the green revolution and the growing rural prosperity, the Post Office Savings Bank is playing a vital role, in mopping up the surplus money for nation-building activities. It holds a sum of Rs. 2,221 crores in the form of deposits in the savings bank and other accounts and outstandings in savings certificates. The number of depositors exceeds 2.4 crores.

Savings is a virtue and a discipline for every citizen. Savings and investment in approved small savings schemes help not only the saver but also the country which has to find resources for the various nation-building schemes to achieve a sustained rate of growth of the national income and to fight the inflationary trends.

The Posts and Telegraphs Department plays an important role in promoting habits of thrift and feel privileged to be associated with the world wide celebrations of the World Thrift Day by bringing out this special commemorative stamp.

बिस्की की शर्तें

यदि विदेशों से नये डाक-टिकट व प्रथम दिवस आवरण भेजने के मांग-पत्र डाक-तार विभाग के पास भेजे जाएं तो उन्हें भारतीय डाक-टिकट संकलन ब्यूरो, बड़ा डाकघर, बम्बई के पते पर भेजा जाना चाहिए और उनके साथ भारत में भुनाया जा सकने वाला बैंक ड्राफ्ट या रेखांकित चेक भी भेजा जाना चाहिए।

TERMS OF SALE

Overseas orders, if placed with the P & T Department, for the supply of the new stamps and First Day Covers should be addressed to the **Indian Philatelic Bureau, G.P.O., Bombay**, and be accompanied by a bank draft or crossed cheque encashable in India.



TECHNICAL DATA

जारी करने की तारीख	...	31-10-1971
Date of Issue	...	31-10-1971
मूल्य वर्ग	...	20 प.
Denomination	...	20 P.
कुल आकार	...	4.06 × 2.28 सें.मी.
Overall Size	...	4.06 × 2.28 cms.
मुद्रण आकार	...	3.80 × 2.00 सें.मी.
Printing Size	...	3.80 × 2.00 cms.
प्रति शीट संख्या	...	50
Number per Issue sheet	...	50
रंग	...	नील धूसर
Colour	...	Blue Grey
छिद्रण	...	14 × 14½
Perforation	...	बिना जलचिह्न वाले डाक-टिकट के चिप-चिपे कागज पर मुद्रित
जलचिह्न	...	बिना जलचिह्न वाले डाक-टिकट के चिप-चिपे कागज पर मुद्रित
Watermark	...	Printed on unwater-marked adhesive stamp paper

मुद्रण प्रक्रिया	... फोटोग्रेव्योर
Printing Process	... Photogravure
मुद्रित टिकटों की संख्या	... 30,00,000
Number Printed	
डिजाइन और मुद्रण	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय
Designed and Printed at	India Security Press

डिजाइन का विवरण

डाक-टिकट क्षैतिज आकार का है और इसमें ग्लोब का चित्र अंकित है जिसके मध्य में एक बचत पेटी और दो हाथ सिक्का पकड़े दर्शाये गए हैं ।

DESCRIPTION OF DESIGN

The design of the stamp is horizontal and depicts a picture of the Globe and a saving box in the middle with two hands each holding a coin.



भारतीय डाक-तार विभाग
INDIAN POSTS & TELEGRAPHS

मूल्य पै०.
Price 10 P.

Designed and produced by the Directorate of Advertising & Visual Publicity, Ministry of I. & B., Govt. of India, New Delhi, for the Indian Posts & Telegraphs Department and printed at Recorder Press, New Delhi.